रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] दिल्ली, सोमवार, जनवरी 14, 2019/पौष 24, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 709

No. 7] DELHI, MONDAY, JANUARY 14, 2019/PAUSHA 24, 1940 [N.C.T.D. No. 709

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला और बाल विकास विभाग

(बाल संरक्षण शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 10 जनवरी, 2019

F.No. 61 (469) DCPCR अमेंड / डीडी (CPU) / DWCD / 2012/37488-500.—बाल अधिकार अधिनियम, 2005 (2006 के 4) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना F. No. U-11030/1 / 2007-UTL दिनांक 15 जनवरी, 2008, के अंतर्गत दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के द्वारा दिल्ली बाल अधिकार आयोग नियमावली, 2008 को निम्नलिखित अनुसार संशोधित किया जा रहा है, अर्थात्: —

लघु शीर्षक और सूत्रपात: —

1. (i) इन नियमों को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियम, 2019 कहा जा सकता है।

(ii) वे दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से और उसके बाद से लागू होंगे।

2. नियम 9 का संशोधन – बाल अधिकार संरक्षण नियम, 2008 के दिल्ली आयोग में (प्रधान नियमों के रूप में संदर्भित), नियम 9 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"9- वेतनऔरभत्ते -"

i) सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के मामले में, वेतन प्रचलित आदेशों के अनुसार अर्थात् अंतिम वेतन आहरित माइनस पेंशन के अनुसार तय किया जाएगा

ii) गैर-आधिकारिक व्यक्ति के मामले में, अध्यक्ष के लिए समेकित वेतन राशि रु 2,00,000 / - प्रति माह (भत्ते के बिना) और प्रत्येक सदस्य के लिए समेकित वेतन राशि रु 1,00,000 / - प्रति माह वेतन (भत्ते के बिना)"।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य सरकार के नाम पर और आदेश द्वारा
जे.के. जैन, संयुक्त निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(CHILD PROTECTION UNIT)

NOTIFICATION

Delhi, the 10th January, 2019

F.No. 61(469)DCPCR Amend/DD(CPU)/DWCD/2012/37488-500.—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Commissions for protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification F. No. U-11030/1/2007- UTL dated the 15th January, 2008, the State Government of the National Capital Territory of Delhi is pleased to amend the Delhi Commission for Protection of Child Right Rules, 2008 as following, namely:-

Short title and Commencement: -

1. (i) These rules may be called the Delhi Commission for Protection of Child Rights (Amendment) Rules, 2019.

(ii) They shall come into force on and from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment of Rule 9** – In the Delhi Commission for Protection of Child Rights, Rules 2008 (hereinafter referred as Principal Rules), for rule 9, the following shall be substituted, namely: -

"9- Salaries & Allowances –

"i) in case of retired Government Servants the pay will be fixed in accordance with the prevailing orders i.e. last pay drawn minus pension.

ii) In case of non-official person, the amount will be Rs. 2,00,000/- per month consolidated without allowances for the Chairperson and Rs. 1,00,000/- per month without allowances consolidated for each Member".

By order and in the name of the State Government of the
National Capital Territory of Delhi

J.K. JAIN, Joint Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.01.18 11:53:13 +05'30'